उत्तराखंड सरकार को महंगा पड़ा महिला की पीठ से घास का गट्ठर उतारना, 24 जुलाई को हैलंग में जुटेंगे राज्य भर के आंदोलनकारी

सलीम मलिक की रिपोर्ट

सुदूर पहाड़ की एक सीधी-साधी घसियारी की पीठ पर लदा घास का गट्ठर उतारना राज्य सरकार के गले की फांस भी बन सकता है। पंद्रह जुलाई को चमोली जिले के हैलंग इलाके में महिला से जोर-जबरदस्ती कर रहे पुलिसकर्मियों ने शायद ही सोचा हो। लेकिन प्रकृति के त्योहार हरेले से एक दिन पूर्व मंदोदरी देवी नाम की इस महिला के साथ हुई पुलिसिया बदसलूकी ने पूरे प्रदेश के लोगों को इतना उद्वेलित कर दिया कि यह मामला निकट भविष्य में सरकार के लिए बड़ी परेशानी के रूप में देखा जाने लगा है।

इस प्रकरण की पृष्ठभूमि की जानकारी के लिए बताते चलें कि उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ शहर के पास टीएचडीसी की पीपलकोटी विष्णुगाड़ नाम की जल विद्युत परियोजना चल रही है। इसी परियोजना के लिए हैलंग नाम की एक जगह पर सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना को संचालित करने वाली कम्पनी के पास इस सुरंग से निकले मलवे को डंप करने के लिए जो स्थान उपलब्ध हैं, वहां मलवे का निपटारा करना खासा महंगा है। इसलिए कम्पनी सुरंग के इस मलवे को अपनी सुविधानुसार सीधे-सीधे अलकनंदा नदी में डंप करने की सोच रही है। लेकिन मलवा खुलेआम नदी के हवाले करने से होने वाले विवाद की वजह से कम्पनी ने बैकडोर का सहारा लेते हुए नदी के किनारे एक स्थान पर इस मलवे को डंप करना शुरू कर दिया जिससे भविष्य में यह मलवा बाढ़ आने पर खुद ही नदी में समा जाए। इस जगह पर गांव वाले अपनी चारागाह होने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि यह उनके पशुओं के लिए बची हुई आखिरी चारागाह है। यदि इस जगह को भी मलवे से बरबाद कर दिया गया तो वह अपने पशुओं के लिए चारा पत्ती लेने कहां जायेंगे ? इस मामले में जिला प्रशासन ने कम्पनी की सुविधा के लिए इस भूमि पर गांव के लिए खेल मैदान विकसित किए जाने की आड़ में यहां पर सुरंग का मलवा डाले जाने की अनुमति पहले ही दे दी है। लेकिन ग्रामीण अब भी इस जगह मलवा डाले जाने का विरोध कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि अधिकांश ग्रामीण इस योजना के समर्थन में हैं और उन्होंने अपनी अनापत्ति प्रशासन को दे दी है। महज कुछ ही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। प्रशासन ने इन महज कुछ ही लोगों को सबक सिखाने और डराने-धमकाने के लिए इस जगह पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के सशस्त्र जवानों के साथ जिले भर के सरकारी अमले को यहां तैनात कर दिया।

15 जुलाई को इसी गांव की तीन महिलाएं और एक पुरुष जिसमें मंदोदरी देवी, लीला देवी, संगीता भंडारी और विपिन भंडारी शामिल थे, को इस जगह से चारा पत्ती लेकर हाइवे पर आते ही सीआईएसएफ और पुलिस के जवानों ने रोक लिया। इन जवानों ने ग्रामीणों से जबरन उनके चारा-पत्ती के गट्ठर छीन लिए। इस दौरान मंदोदरी की इन जवानों से तीखी झड़प भी हुई। जबकि एक अन्य महिला इस बेबसी पर अपनी आंखों के कोर से निकले आंसू साफ करती नजर आई। स्तब्ध कर देने वाला यह दृश्य पब्लिश खबर के साथ वीडियो में है। महिलाएं अपना घास का गट्ठर न छीने जाने की गुहार लगाती रहीं लेकिन घास लाने वाली महिलाओं के सम्मान में चुनाव से पूर्व घसियारी योजना लाने वाली पुष्कर सिंह धामी की सरकार के इन जवानों के सामने यह घसियारी महिलाएं बेबस ही बनकर रह गई।

खाकी वर्दीधारियों ने न केवल इनके घास के गट्ठर छीने बल्कि इन्हें खूंखार मुजरिमों की तरह तहसीलदार की गाड़ी में भरकर सीधे जोशीमठ शहर के पुलिस थाने पहुंचा दिया गया। इन महिलाओं को छः घंटे तक पुलिस वाहन कस्टडी और थाने में बिठाने के बाद इनका पुलिस एक्ट के तहत 250-250 रुपये का चालान कर छोड़ा गया। इस मामले में जोशीमठ के थानाध्यक्ष विजय भारती का जो बयान आया है उसके अनुसार हेलंग में कुछ परिवारों की ओर से सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है। यहां खेल मैदान और अन्य विकास योजनाओं का निर्माण प्रस्तावित है। निर्माण कार्य के दौरान ये महिलाएं चारापत्ती लेने गई थीं। शांति व्यवस्था बनाने के लिए उन्हें वाहन से थाने में लाया गया। उन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया गया।

मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे उत्तराखंड की आंदोलनकारी ताकतें में उबाल आ गया है। पुलिसकर्मियों द्वारा महिलाओं से घास के गट्ठर छीने जाने का मामला हैलंग से निकलकर राज्य की राजधानी देहरादून तक में तूल पकड़ने लगा है। उत्तराखंड महिला मंच सहित तमाम संगठन इसके खिलाफ लामबंद होने लगे हैं। देहरादून में उत्तराखंड महिला मंच संगठन ने इस घटना के विरोध में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। मंच का कहना है कि 15 जुलाई को जोशीमठ प्रखंड के हेलंग गांव में जंगल से घास ला रही महिलाओं से न सिर्फ उनके घास के गट्ठर छीनते पुलिस व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान दिख रहे हैं बल्कि वीडियो में ही दिखता है कि एक महिला रो रही है, दूसरी के साथ छीना झपटी हो रही है।

उन्होंने कहा कि यह दृश्य इस राज्य में, जो कि महिलाओं के आंदोलन व उनकी शहादत व कुर्बानियों के बदौलत बना, देखना बहुत शर्मनाक है दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी कोई सफाई नहीं हो सकती। महिला मंच की प्रदेश अध्यक्ष कमला पंत ने कहा कि उत्तराखण्ड में जल विद्युत परियोजनाओं के नाम पर हजारों हजार नाली नाप भूमि, जंगल, चरागाह की भूमि, पनघट, मरघट, पंचायत की भूमि, कम्पनियों को पहले ही दे दी गयी है। इसके बाद भी कम्पनियों की नीयत लोगों की सामूहिक हक-हकूक की भूमि को भी हड़प लेने की है। इससे आम ग्रामीणों के सम्मुख घास चारा लकड़ी का संकट पैदा हो गया है। यह घटना इसी का परिणाम है। दूसरी तरफ बागेश्वर में भी सवाल संगठन ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर जोशीमठ के हेलंग में घास लेकर आ रहीं महिलाओं को रोकने की जांच कर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है।

सवाल संगठन के अध्यक्ष रमेश पांडेय कृषक, किसान क्लब देवनाई के अध्यक्ष सुंदर बरोलिया, भुवन पाठक, कांग्रेस नेता रंजीत दास, लक्ष्मण आर्या, वन पंचायत सरपंच अर्जुन राणा, देवानंद आदि ने एसडीएम को ज्ञापन देकर घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इल्जाम लगाया है कि प्रदेश के वाशिंदों को उनके हक हकूक से जबरन वंचित रखने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से घटना की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। कत्यूर घाटी गरुड़ के भी विभिन्न संगठनों ने भी संदन मिश्रा के नेतृत्व में एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में उन्होंने महिलाओं से ज्यादती करने वालों को कड़ी सजा दिलाने और बांध निर्माण कंपनी की जांच कराने की मांग की है।

देहरादून के वरिष्ठ पत्रकार त्रिलोचन भट्ट के अनुसार विष्णुगाड़ पीपलकोटी परियोजना के तहत हेलंग में सुरंग बनाने का कार्य कर रही कम्पनी द्वारा खेल मैदान बनाने के नाम पर जहां डम्पिंग जोन बनाया जा रहा है, वह इस गांव के लोगों चारागाह के तौर पर अंतिम विकल्प है। यहां इन लोगों ने जमीन पर वृक्षारोपण कर इस भूमि को हरा-भरा बना रखा है। लेकिन डम्पिंग जोन के नाम पर कम्पनी द्वारा यहां के हरे पेड़ काटकर चारागाह के इस अंतिम विकल्प को खत्म किया जा रहा है।

त्रिलोचन ने उत्तराखण्ड के राजकीय पर्व हरेला के अवसर पर यहां की हरियाली नष्ट करने और हरियाली के रक्षकों पोषकों के साथ भी बदसलूकी कर उन्हें गिरफ्तार करने को राज्य की विडंबना बताते हुए इस घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

इसके अलावा राज्य के तमाम आंदोलनकारी संगठनों ने हैलंग घटना के विरोध में हैलंग कूच का भी आह्वान किया है। समाजवादी लोक मंच के मुनीष कुमार ने बताया कि 24 जुलाई को प्रस्तावित इस कूच के दौरान व्यापक आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।

सुकमा जिले में नक्सल हमले के आरोपी बनाए गए 121 ग्रामीण एनआईए कोर्ट से दोषमुक्त

तामेश्वर सिन्हा

बस्तर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के बुर्कापाल में हुए नक्सल हमले के आरोपी बनाए गए 121 ग्रामीण दोष्मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। ये फैसला NIA की विशेष अदालत ने सुनाया है। NIA कोर्ट के न्यायाधीश दीपक कुमार देशलहरे की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। घटना अप्रैल 2017 की है। नक्सलियों ने बुर्कापाल में जवानों पर हमला कर दिया था। जिसमें 25 जवानों की शहादत हुई थी। घटना के आरोप में 2 महीने के अंदर 121 ग्रामीणों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। किसी को नक्सली तो किसी को नक्सल सहयोगी बताकर पकड़ा गया था। दंतेवाड़ा NIA कोर्ट में इसका ट्रायल के बाद फैसला आया है।

सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीणों की तरफ से इस केस की वकील बेला भाटिया ने बताया कि, दंतेवाड़ा की NIA कोर्ट का फैसला ग्रामीणों के पक्ष में आया है। साक्ष्य न मिलने पर 121 ग्रामीणों को दोषमुक्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बुर्कापाल का ये केस बस्तर का एक उदाहरण है यह बताने के लिए कि बस्तर में पुलिस की प्रक्रिया कैसे चलती है। साल 2017 की घटना थी।

2 महीने में 121 ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया और कई कठोर धाराएं लगा दीं। साल 2017 की घटना का ट्रायल साल 2021 को दंतेवाड़ा को NIA कोर्ट में हुआ। कोई ठोस सबूत न मिलने पर ग्रामीणों को दोषमुक्त कर दिया गया है।

दरअसल, 24 अप्रैल 2017 को सुकमा जिले के बुर्कापाल में CRPF की 74वीं बटालियन के जवान सड़क निर्माण सुरक्षा में निकले थे। जवान खाना खाने बैठे। पहले से घात लगाए नक्सलियों ने जवानों पर हमला कर दिया था। इस घटना में 25 जवानों की शहादत हुई थी और 7 जवान घायल हुए थे। जबकि एक माओवादी भी मारा गया था। पूरी घटना का वीडियो भी नक्सलियों ने साल भर बाद जारी किया था। मई और जून 2017 में बुर्कापाल और आस-पास के गांवों से 120 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया।

फिर एक महिला को नक्सली बताकर पकड़ा गया। इन 121 लोगों पर UAPA की धारा 38,39, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम की धाराएं 8 (1) (3) (5), आर्म्स एक्ट (धाराएं 25, 27) विस्फोटक प्रदार्थ अधिनियम (धाराएं 3, 5), भारतीय दंड संहिता (धाराएं 147, 148, 149, 120(B), 307, 302, 396, 397) के तहत केस दर्ज किया गया, इस केस को ग्रामीणों की ओर से बेला भाटिया समेत 5 से ज्यादा वकीलों की टीम लड़ रही थी।

द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ लुलू

गिरीश मालवीय

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल टैक्स हैवन देश केमैन आईलैंड में जीएनवाई एशिया फंड नाम की हेज फंड कंपनी चलाते हैं। यह 2016 में बनी है। इस कंपनी में विवेक डोभाल के अलावा दो डायरेक्टर हैं, जिसमें एक डॉन डब्ल्यू. इबैंक्स हैं। यह शख्स वही है, जिसका नाम पनामा और पैराडाइज पेपर में आ चुका है। और दूसरे हैं मोहम्मद अल्ताफ़ मुसलियाम वीटिल।

कमाल की बात यह है कि मोहम्मद अल्ताफ़ मुसलियाम वीटिल उत्तर प्रदेश में 2016 में पंजीकृत हुई LULU INDIA SHOPPING MALL PRIVATE LIMITED में भी डायरेक्टर के पद पर विराजमान हैं। इसके अलावा वे लुलु ग्रुप की अन्य चार कम्पनियों में भी डायरेक्टर पद पर आसीन हैं जो भारत में ही रजिस्टर्ड है।

हम यहां उसी लखनऊ के लुलु मॉल की बात कर रहे हैं जो इस वक्त चर्चाओं के केन्द्र में है, यह लुलु ग्रुप की ही एक संपत्ति है। .....केरल के एनआरआई यूसुफ अली अबु धाबी स्थित लू लू ग्रुप के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं। अगर आप लुलु ग्रुप को मात्र लखनऊ के माल तक सीमित कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। लुलु ग्रुप उत्तर प्रदेश के कुछ और बड़े शहरो में भी अपने मॉल बना रहा है।

दिसंबर 2021 में, लुलु समूह अहमदाबाद के पास एक आधुनिक शॉपिंग मॉल स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा कर चुका है।

जम्मू कश्मीर में, जहां भारत का कोई उद्योगपति निवेश नही करता, वहां भी लुलु समूह ने जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें श्रीनगर में एक खाद्य प्रसंस्करण और रसद केंद्र स्थापित करने के लिए 200 करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया है। यह समझौता इसी साल जनवरी में हुआ है।

शायद 2019 की वह तस्वीर आपको याद हो जब डोभाल साहब 370 हटने के बाद कश्मीर में 'मिशन अमन' पर निकले थे और वहां के स्थानीय मुसलमानो के साथ घुल मिल रहे थे।

दरअसल अजीत डोभाल जी के पूरे अरब जगत से बेहद मधुर रिश्ते हैं। अरब जगत संबंधित मामले वही हैंडल करते हैं। जब धारा 370 हटाई गई थी तो अजित डोभाल जी सउदी प्रिंस से मुलाकात कर उन्हें भारत के कंसर्न समझा रहे थे। इसी दौरे में उन्होंने अबू धाबी के अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद से भी मुलाकात की थी। दरअसल, कुछ ही महीने पहले यूएई का सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी को दिया गया था ..... यहां भी डोभाल साहब की मेहनत साफ़ नजर आती है।

अजित डोभाल जी के दो पुत्र हैं। उनके पहले पुत्र शौर्य डोभाल जी की पार्टनरशिप एक सऊदी प्रिंस के साथ है और दूसरे पुत्र विवेक डोभाल जी के यूएई के व्यापार जगत के साथ महत्वपूर्ण रिश्ते हैं।

यह रिश्ता क्या कहलाता है ?